

अनर्धितरति जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम

अक्सर देश में जनसंख्या नर्धितरण के मुद्दे पर प्रारंभ होने वाले वैचारिक विमर्श को कुछ लोगों द्वारा एक हक छीनने जैसी प्रतिक्रिया मलिती है। ऐसा लगता है जैसे उनके नर्धि जीवण पर हमला कया गया हो। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग इसे धार्मिक रंग चढ़ाने से भी पीछे नहीं हटते और ज़रूरी मुद्दों के प्रतजागरूकता को लेकर समाज को भटकाने का प्रयास करते हैं।

अब सबसे पहले यह जानते हैं क अनर्धितरति जनसंख्या वृद्धि कया होती है? जनसंख्या में अनर्धितरति वृद्धि एक सापेक्ष शब्द है। देश में उत्पादति खाद्यान्नो या उपलब्ध संसाधनों के परपिरेक्ष्य में अधिक तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या आर्थिक वृद्धि दर और सामाजिक संतुलन दोनों को नकारात्मक ढंग से प्रभावति करती है। वस्तुतः स्वास्थ्य संबंधी प्रगत दर के कारण घटती मृत्यु दर और स्थायी जन्म दर इस वसिगत के मूल में स्थति है। यद्यपि मानव संसाधन कसी भी देश की प्रगति के लिये आवश्यक है तथापि इसमें कमी या वृद्धि से उस देश का विकास प्रभावति हो जाता है। अतएव एक आदर्श स्थति के नर्माण हेतु इसमें संतुलन आवश्यक है।

जनसंख्या की दृष्टि से भारत का वशिव में द्वितीय स्थान है एवं जनघनत्व के मामले में भी भारत काफी ऊपर है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि एवं अन्य संसाधनों पर काफी दबाव महसूस कया जाता रहा है। कसी भी देश की जनसंख्या को घटाने या बढ़ाने में मुख्यतः तीन कारक प्रमुख होते हैं- जन्म दर, मृत्यु दर तथा आवास-प्रवास। जन्म दर अधिक एवं मृत्यु दर कम होने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है एवं जन्म दर कम हो तथा मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या में कमी आती है। इसी प्रकार यदि दूसरे देशों से आने वालों की संख्या वदिश जाने वाले लोगों की संख्या से अधिक होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी एवं विपरीत स्थति में जनसंख्या में कमी आएगी।

संयुक्त राष्ट्र की द वरल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस 2019 : हाईलाइट्स नामक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2027 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की कुल आबादी 1.64 बलियन के आँकड़े को पार कर जाएगी एवं वैश्विक जनसंख्या में 2 बलियन हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी रेखांकति कया गया है क इस अवधि में भारत में युवाओं की बड़ी संख्या मौजूद होगी, लेकिन आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में इतनी बड़ी आबादी की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे- भोजन, आश्रय, चकितिसा और शक्ति को पूरा करना भारत के लिये सबसे बड़ी चुनौती होगी। उच्च प्रजनन दर, बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और बढ़ते प्रवासन को जनसंख्या वृद्धि के कुछ प्रमुख कारणों के रूप में बताया गया है।

गौरतलब है क भारत में जनसंख्या समान रूप से नहीं बढ़ रही है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, संपत्ति तथा धन के आधार पर कुल प्रजनन दर (TFR) में विभिन्नता देखने को मलिती है। यह सबसे नर्धन समूह में 3.2 बच्चे प्रतमहिला, मध्य समूह में 2.5 बच्चे प्रतमहिला तथा उच्च समूह में 1.5 बच्चे प्रतमहिला है। इससे पता चलता है क समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों में जनसंख्या वृद्धि अधिक देखने को मलिती है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से गरीबी, भूख और कुपोषण की समस्या को प्रभावी ढंग से दूर करने और बेहतर स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण शक्ति प्रदान करने में बाधा आती है। इससे सतत् विकास लक्ष्य (SGD) 1, 2, 3 और 4 प्रतकूल रूप से प्रभावति हो रहे हैं।

जनसंख्या वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी, पर्यावरण का अवनयन, आवासों की कमी, नर्धन जीवन स्तर जैसी समस्याएँ जुड़ी रहती हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है। यह गरीबी और अभाव, अपराध, चोरी, भ्रष्टाचार, कालाबाज़ारी व तस्करी जैसी समस्याओं को जन्म देती है।

पर्यावरण की दृष्टि से भी जनसंख्या वृद्धि हानिकारक है। बढ़ती आवश्यकताओं के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कया जा रहा है जिसके परिणाम वनिशकारी सिद्ध हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि को जल-प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण के लिये भी दोषी माना जा रहा है।

जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख चुनौतियाँ

- **स्थिर जनसंख्या** : स्थिर जनसंख्या वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है क सर्वप्रथम प्रजनन दर में कमी की जाए। यह बहिर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में काफी अधिक है, जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- **जीवन की गुणवत्ता** : नागरिकों को न्यूनतम जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के लिये शक्ति और स्वास्थ्य प्रणाली के विकास पर नर्धन करना होगा, अनाजों और खाद्यान्नो का अधिक-से-अधिक उत्पादन करना होगा, लोगों को रहने के लिये घर देना होगा, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति बढ़ानी होगी एवं सड़क, परिवहन और वदियुत उत्पादन तथा वतिरण जैसे बुनियादी ढाँचे को मज़बूत बनाने पर काम करना होगा।
- नागरिकों की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने और बढ़ती आबादी को सामाजिक बुनियादी ढाँचा प्रदान करके समायोजित करने के लिये भारत को अधिक खर्च करने की आवश्यकता है और इसके लिये भारत को सभी संभावति माध्यमों से अपने संसाधन बढ़ाने होंगे।
- **जनसांख्यिकीय विभाजन** : बढ़ती जनसंख्या का लाभ उठाने के लिये भारत को मानव पूंजी का मज़बूत आधार बनाना होगा ताक वे लोग देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें, लेकिन भारत की कम साक्षरता दर (लगभग 74 प्रतशित) इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।

- **सतत शहरी विकास** :वर्ष 2050 तक देश की शहरी आबादी 7 मिलियन तक हो जाएगी, जिसके चलते शहरी सुविधाओं में सुधार और सभी को आवास उपलब्ध कराने की चुनौती होगी और इन सभी के लिये पर्यावरण को भी मद्देनजर रखना ज़रूरी होगा ।
- **असमान आय वितरण** :आय का असमान वितरण और लोगों के बीच बढ़ती असमानता अत्यधिक जनसंख्या के नकारात्मक परिणामों के रूप में सामने आएगी ।

हालाँकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मानव संसाधन सबसे बड़ा और प्रमुख संसाधन होता है । इस दृष्टि से भारत की स्थिति चिंताजनक नहीं, बल्कि अग्रणी होनी चाहिये, क्योंकि भारत की विशाल जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत तेज़ी से बढ़ रहा है । इसे देखते हुए सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जड़ जनसंख्या नहीं, अपितु भ्रष्टाचार, संसाधनों का असमान वितरण, गरीबी-अमीरी के बीच बढ़ती खाई एवं वजिज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अल्प विकास को माना जा सकता है ।

जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Divided)

भारत में युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो अकुशल, बेरोज़गार सेवाओं और सुविधाओं पर भार जैसा है तथा अर्थव्यवस्था में उनका योगदान न्यूनतम है । किसी भी देश के लिये उसकी युवा जनसंख्या जनसांख्यिकीय लाभांश होती है, यदि वह कुशल रोज़गारयुक्त और अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली है ।

हालाँकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि फिलहाल भारत अपनी तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या को विकास की सीढ़ी नहीं बना पाया है, इसलिये भारत को अभी जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है । सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ खाद्यान्न की सुनिश्चिता, कृषि को लाभकारी बनाना एवं कीमतों पर नियंत्रण जैसे उपाय करने की आवश्यकता है । वन और जल-संसाधनों का उचित प्रबंधन कया जाना चाहिये । अमूरत, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया और सतत विकास लक्ष्य जैसी योजनाएँ निश्चित रूप से देश की सामाजिक आधारिक संरचना को बढ़ाने में सहायता करेंगी । जनसंख्या में कमी, अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, सार्वभौमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सरकारों और मज़बूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है । जनसंख्या समस्या समाधान का श्रेष्ठतम तरीका है कि स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाओं के प्रसार और गुणवत्ता में तेज़ी लाई जाए ।

शिक्षा है न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये बल्कि प्रजनन क्षमता में गिरावट हेतु भी बहुत महत्वपूर्ण । बेहतर शिक्षित महिला परिवार नियोजन के संबंध में सही निर्णय ले सकेंगी । जब तक महिलाएँ कार्यबल का हिस्सा नहीं होंगी कोई भी समाज प्रजनन दर में कमी नहीं ला सकता । ऐसे में प्रभावी नीतियाँ बनाकर कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि की जानी चाहिये । जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे को न केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बल्कि राज्य के दृष्टिकोण से भी देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न राज्यों को जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु अलग-अलग कदम उठाने हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है । इन सब पर्याप्तों से जनसंसाधन के गुणात्मक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और सामाजिक परिवर्तन की दिशा सुनिश्चित हो सकेगी । सरकार सहित राजनेताओं, नीति-निर्माताओं और आम नागरिकों सभी को साथ मलिकर एक ठोस जनसंख्या नीति का निर्माण करना होगा ताकि देश की आर्थिक विकास दर बढ़ती आबादी के साथ तालमेल स्थापित कर सके ।